निर्यातकों के लिए पांच साल तक बढ़ सकती है ब्याज समानीकरण योजना

नई दिल्ली। वाणिज्य मंत्रालय निर्यात को बढ़ावा देने के लिए रुपया निर्यात कर्ज पर ब्याज समानीकरण योजना को अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ाने की मांग कर सकता है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, योजना 30 जून को समाप्त हो रही है। योजना अच्छी चल रही है और निर्यातकों को मदद मिल रही है।

अधिकारी ने कहा, 8 दिसंबर, 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने योजना को 30 जून तक जारी रखने के लिए 2,500 करोड़ रुपये के अतिरिक्त आवंटन को मंजूरी दी। यह

30 जून को समाप्त हो रही है रुपया निर्यात कर्ज योजना

योजना चिन्हित क्षेत्रों के निर्यातकों और सभी एमएसएमई निर्माता निर्यातकों को ऐसे समय में प्रतिस्पर्धी दरों पर रुपया निर्यात ऋण का लाभ उठाने में मदद करती है जब वैश्विक अर्थव्यवस्था विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रही है। इस योजना के तहत निर्यातकों को ब्याज समानीकरण योजना के तहत शिपमेंट से पहले और बाद में रुपया निर्यात कर्ज के लिए सब्सिडी मिलती है। एजेंसी